

पीओके में अशांति

अमित शाह का बयान

पाक अधिकृत कश्मीर-पीओके में जनता का गुस्सा तथा व्यापक अराजकता को देखते हुए अमित शाह ने कहा है कि भारत इसे अपने साथ शामिल कर लेगा। वर्तमान समय में कश्मीर घाटी में शांति एवं सद्व्यवना व्याप्त है, पर एलओसी के पार पीओके में जनता के साथ पुलिस व अर्धसैनिक बलों के बीच टकराव से अराजकता की स्थिति व्याप्त है। ऐसे में भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोर दिया है कि यह क्षेत्र 'भारत का है और हम इसे फिर अपने साथ शामिल कर लेंगे।' उनके इस बयान से संवेदनशील इतिहास के विवादित क्षेत्र पर फिर बहस तेज हुई है। विभाजन के बाद अन्य ऐसे राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर की देशी रियासत को भारत या पाकिस्तान के साथ विलय का विकल्प दिया गया था। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह शुरूआत में तो 'स्वतंत्र' रहना चाहते थे, पर पाकिस्तान-समर्थित कबीलाई उत्तरवादियों की घुसपैठ के कारण उन्होंने अक्टूबर, 1947 में भारत में विलय का फैसला किया। इसके कारण भारत-पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ और संयुक्त राष्ट्रसंघ के आहान पर युद्धविराम के पश्चात एलओसी निर्धारित की गई। इससे यह क्षेत्र भारतीय जम्मू कश्मीर तथा पीओके में विभाजित हो गया। हालांकि, भारत ने अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, पर लगभग एक तिहाई क्षेत्र पर पाकिस्तानी कब्जा बना रहा जिसे उसने 'आजाद जम्मू कश्मीर' व गिलगिट-बालिस्तान का नाम दिया। इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोण से पीओके जम्मू कश्मीर का अखंड अंग है और उसे भारत में शामिल करना ऐतिहासिक, विधिक व नैतिक आधार पर उचित क्षेत्र संबंधी दावा है। भारतीय संसद ने इस पर सर्व-समत प्रस्ताव पास किया है। लेकिन विपक्षी



मंचों पर उठाता रहा है। उसने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने के मुद्दे पर भी हायतोबा मचाई, पर उसे इस्लामी देशों का भी साथ नहीं मिला। जहां जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 हटने के बाद से शांति, लोकतंत्र और प्रगति की राह पर तेज़ी से अग्रसर है, वहाँ बदलाल पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में जनता को दो जून की रोटी भी मुहाल है। वहाँ आटे की कीमतों, बिजली की दरों तथा पाकिस्तान सरकार द्वारा थोपे करारों के विरोध में व्यापक जनान्दोलन हुआ। पुलिस व पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ मुठभेड़ में तीन प्रदर्शनकारियों के मारे जाने के बाद आंदोलन और उग्र हो गया। सालों से अशांत इस क्षेत्र में मानवाधिकार व लोकतांत्रिक अधिकारों के उल्लंघनों तथा पाकिस्तानी अवस्थापना द्वारा जनता के स्वर दबाने की घटनायें बार-बार सामने आई हैं। यहाँ 'गिलगिट बाल्टिस्तान मूवर्मेंट' जैसे नागरिक अधिकार आंदोलन पाकिस्तानी अत्याचारों का लगातार मुकाबला कर रहे हैं। इन आंदोलनों ने भारत सरकार से बार-बार आह्वान किया है कि वह उनके उत्पीड़न को दुनिया भर में डजागर करे। पीओके में जनता का बढ़ा हिस्सा भारत वाले जम्मू कश्मीर में विलय का इच्छुक है और उसकी आवाज मुखर रूप से दुनिया के सामने आ रही है। ऐसे में अमित शाह के बयान को संकुचित चुनावी दृष्टिकोण के बजाय व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सोने की भूमिका

व्यावहारिक घरेलू बचतकर्ताओं की तरह भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में स्वर्ण भंडारों की उपयोगिता को देखते हुए आरक्षित स्वर्ण भंडार बढ़ा कर 817 मीट्रिक टन कर दिया है।



भा रतीय परिवारों द्वारा अपनी संपदा सुरक्षित रखने के रणनीतिक कदम की तरह भारतीय रिजर्व बैंक-आरबीआई ने सक्रिय रूप से स्वर्णी भंडार बढ़ा कर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह साहसी पहल व्यावहारिक घेरलू बचतकर्ताओं की आदत का प्रतीक है। केन्द्रीय बैंक ने संभावित आर्थिक उथलपुथल से स्वयं को सुरक्षित रखने की दिशा में यह कदम उठाया है। अब आरबीआई ने आरक्षित स्वर्ण भंडार बढ़ा कर 817 टन कर दिया है। इस बढ़ोत्तरी के पीछे अनेक कारण हैं जिनमें पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, फिलिस्तीन पर इजराइल का हमला, रूस-यूक्रेन युद्ध तथा लगातार जारी मद्रास्फीति शामिल हैं।



डालर को अस्थिरता का दखत हुए अपने विदेशी मुद्रा भंडारों का विविधीकरण किया जा सके।' अमेरिका में साल दर साल मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है और यह फरवरी में 3.2 प्रतिशत पर पहुंच गई। फेडरल रिजर्व द्वारा 2022 में ब्याज दरें बढ़ाना शुरू करने के बाद से उसने जुलाई, 2023 में दरें बढ़ा कर 5.25 प्रतिशत के बजाय 5.5 प्रतिशत कर दीं। अमेरिका में चुनाव को देखते हुए वह अपना मुद्रा भंडार बढ़ा रहा है। इस साल की शुरुआत से सोने की कीमतों में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है।

इस प्रकार इसे मुद्रास्फीति के खिलाफ एक बाड़ तथा बढ़ती राजनीतिक व अर्थिक अनिश्चितता में सुरक्षित स्वर्ण की तरह देखा जा रहा है। सोने की कीमतें बढ़ने का प्रमुख कारण केन्द्रीय बैंकों द्वारा इसकी भारी मात्रा में खरीद तथा सुरक्षित-स्वर्णों में संपत्ति की बढ़ती मांग है। भारत में सोने की कीमतों में 2024 में काफी उछाल आया है। इसके कारण अक्षय तृतीया के दो दिन पहले इसकी कीमत अभूतपूर्व रूप से अब तक के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। परंपरागत रूप से सोने की खरीद सबसे उच्च स्तर 73,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। इस प्रकार इसकी कीमतों में केवल एक साल के भीतर 21.1 प्रतिशत की जबरदस्त

वृद्धि हुई। हालांकि, 10 मई का अक्षय तृतीया वाले दिन इसकी कीमत में थोड़ी कमी आई और यह 72,788 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पिछले 6 महीने में सोने की घरेलू कीमतों में उछाल आया और यह 54,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़ कर रिकार्ड 73,958 रुपये पर पहुंच गई।

कोई भी समझ सकता है कि सोने की तुलना में किसी भी चीज की कीमतें इतनी तेजी से नहीं बढ़ती हैं और ऐसे में आरबीआई की व्यावहारिकता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। वर्तमान समय में एक डालर 83.88 रुपये का है। 6 महीने में रुपये की कीमत में वृद्धि की उम्मीद है और यह 82.50 पर पहुंच सकता है। एक साल में 1.1 प्रतिशत वृद्धि के साथ यह 82 रुपये तक पहुंच सकता है जो 1.7 प्रतिशत वृद्धि होगी। इसका अर्थ है कि आरबीआई के डालर भंडार का मूल्य एक साल में लगभग 2 प्रतिशत कम हो जाएगा। इसलिए आरबीआई ने डालर की तुलना में ज्यादा सोना खरीदने का निर्णय किया। इसमें प्रति 10 ग्राम पर 73,000 रुपये खर्च करने पर भी 20 प्रतिशत का लाभ होगा। यह समझदारी वाली अर्थव्यवस्था है। आरबीआई ने अपने भंडारों में विविधता लाने के एसोना खरीदना तेज कर दिया है। विदेशी

भंडार में साने के मूल्य में 3 बिलियन लर की वृद्धि हुई है और यह 648.5 बिलियन डालर हो गई है। आरबीआई ने विधीकरण तथा मुद्रास्फीति से सुरक्षा लिए 2024 की शुरुआत में ज्यादा ता खरीदा है।

विश्व स्वर्ण परिषद-डब्ल्यूसी के युसार जनवरी-मार्च में आरबीआई द्वारा ता खरीद बढ़ कर 19 टन पहुंच गई। ती की तुलना में पूरे 2023 साल में उसने वल 16 टन सोना खरीदा था। लूजीसी के अनुसार, सर्वाधिक स्वर्ण द्वारा वाले देशों में अमेरिका 8,133 टन साथ सबसे ऊपर है, इसके बाद रनी, इटली, फ्रांस और रूसी संघ का न है जिनके पास क्रमशः 3366.49, 51.84, 2436.01 व 2271.16 टन ता है। केन्द्रीय बैंकों द्वारा सोने की तीद में वृद्धि अमेरिका द्वारा रूस पर लगे तंबधों के बाद आई। ये प्रतिबंध रूस यूक्रेन पर हमले के कारण लगे और में रूसी आरक्षित डालर भंडार फ्रीज ना तथा कच्चे तेल समेत उसके त्वपूर्ण वस्तु व्यापार पर प्रतिबंध मिल है। इन कदमों के वैश्विक योगीत प्रभाव काफी व्यापक थे जिनसे रचमी वित्तीय संस्थानों की संकटग्रस्त भवित उजागर हो गई। इसके चलते शेर्यों निवेश का विकल्प ज्यादा जोखिम

है। नवीनतम फेडरल रिजर्व डेटा के सार चीन ने अमेरिकी ट्रेजरी स्पूरिटीज से 22.7 बिलियन डालर तरिकत निकाले और अपनी कुल रिल्डिंग घटा कर 775 बिलियन डालर दी। इस कमी के बावजूद चीन अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा कर्जदाता अमेरिकन फेडरल रिजर्व डेटा के सार चीन डालर पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। 'आईसीआईसीआई डाइरेक्ट डी' के अनुसार आरबीआई अमेरिकी नर पर अपनी निर्भरता घटाने के साथ ने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता ना चाहता है। सोना स्थायित्र प्रदान ता है और इसे सीधे किसी एक मुद्रा नहीं जोड़ा जा सकता है। आर्थिक निश्चितता या डालर मूल्य में उत्तर-वाव के समय यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सोने को मुद्रास्फीति के खिलाफ़ इस समझा जाता है। जब मुद्रास्फीति के अपन मुद्राओं का मूल्य गिरता है तब भी ये का मूल्य बना रहता है या बढ़ता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की दो शक्ति की रक्षा करता है। आरबीआई का कहना है कि स्वर्ण भंडार फौलियों में विविधता से भारतीय व्यवस्था में विदेशी निवेशकों का बावस बढ़ता है। यह भारत की मजबूत नीतीय स्थिति और स्थायित्व का प्रतीक है विदेशी निवेश को आकर्षित करती है। द्वार्थांकित अनुज्ञान समाप्तन नर्दीने वे

हालांकि, अब ज्यादा सामान्य नहा है, अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में अब भी सोने प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे में वश्यकता होने पर अरक्षित स्वर्ण ग्राह के साथ भारत दूसरे देशों का कर्जा भरा कर सकता है। यदि कोई देश रुपया बचाकर करने को तैयार न हो तो उसे भारत द्वारा दिया जा सकता है। दुनिया की भू-विनीतिक स्थिति को देखते हुए अगले वर्ष साल उथलपुथल वाले हो सकते हैं और यह सोना अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बदल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा सकता है। वर्तमान समय में आईटी, डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट, उद्योग और बाजारों में उथलपुथल है। इनको शांत होने में कुछ समय लगा। ऐसे समय में कागजी मुद्रा की नीति में सोने की मांग और बढ़ाने की बाबता है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक-रबीआई ने आरक्षित स्वर्ण भंडार बढ़ाने सही कदम उठाया है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तथा हम देश की अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख स्थान करेंगे।

भारत-ईरान के बीच चाबहार समझौता

जा भारत क सबस नजदाक स्थित ह, जा भारत की मध्य एशिया तक पहुंच और इस क्षेत्र के राज्यों के लिए हिंद महासागर में पहुंच के लिए महत्वपूर्ण है। चाबहार परियोजना पहली बार 2003 में ईरान और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मंच के रूप में समाने आई थी, जब पीएम वाजपेयी और ईरानी समकक्ष हसन रुबानी ने दोनों देशों के बीच परिवर्तनकारी रणनीतिक सहयोग खाका का अनावरण किया ईरान और भारत के बीच हस्ताक्षरित 2003 के दिल्ली घोषणापत्र में दोहराया गया है कि मेलक.

जरांज और डेलाराम के माध्यम से चाबहार मार्ग विकसित करने के लिए भारत, ईरान और अफगानिस्तान की सरकारों के बीच हाल ही में हुआ त्रिपक्षीय समझौता क्षेत्रीय व्यापार और पारगमन को सुगम बनाएगा, जिसमें अफगानिस्तान और मध्य एशिया भी शामिल है, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी।

हालांकि, वाजपेयी सरकार के बाद,

An aerial photograph of a bustling port terminal. The central feature is a large, rectangular industrial area surrounded by a breakwater. On the left side, several white lattice-boom cranes are lined up along a quay, ready to handle cargo. The ground is covered with a dense grid of shipping containers in various colors. In the background, across the water, a city skyline with numerous skyscrapers is visible under a clear blue sky.

परियोजना पर स्थानांतरित हो गया, जो आंशिक रूप से घरेलू राजनीति और एक नई विश्व व्यवस्था से प्रभावित था। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक इस एकीकृत बहु-मॉडल चाबहार परियोजना को प्रमुखता नहीं मिली। 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति डिंक

लकर बहुत उत्सुक नहीं था), लाकन अफगानिस्तान तक स्वतंत्र पहुंच ने हिचकिचाहट को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एशिया में महत्वपूर्ण प्रगति का है। इरान ने राष्ट्रपति ने इस साल फरवरी में चीन में एक उच्च-स्तरीय आर्थिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जबकि उन्होंने दोहराया

2017 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने चाबहार में परिवहन और पारगमन गलियारे की स्थापना पर अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए दूसरी मंत्रिस्तरीय त्रिपक्षीय बैठक की। त्रिपक्षीय बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया, क्षेत्रीय अर्थिक संपर्क के लिए एक केंद्र के रूप में चाबहार के महत्व और इस उद्देश्य की दिशा में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मंत्रियों ने चाबहार के माध्यम से भारत से अफगानिस्तान तक गेहूं के हाल ही में सफल पारगमन में तीनों देशों के संयुक्त प्रयासों की सराहना की। लगभग सात साल बाद भारत को महत्वपूर्ण परिचालनों को संभालने के लिए चाबहार बंदरगाह तक परी पहुंच मिली।

यह याद दिलाना ज़रूरी है कि चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड पहल को निर्णयकर्ता हुआ करता था और अब वह इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए तैयार है।

होर्डिंग हार्डसा

मोदी की चुनौती

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी सरकार द्वारा बनाए सीएए कानून को समाप्त करने की विपक्ष की चुनौती पर समूचे विपक्ष को ललकारते हुए कहा है कि कोई मार्ई का लाल सीएए कानून को खत्म नहीं कर सकता। आज जिस तरह विपक्षी दलों ने वोटबैंक की राजनीति में हिंदू-मुसलमान को लड़ा कर धर्मनिरपेक्षता का ऐसा चोला पहन लिया है जिसे मोदी इनके शरीर से हटाना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर विपक्षी दल मुस्लिम तुषीकरण कर सभी गैर-मुस्लिमों को नीचा दिखाने का काम करते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वादा किया था कि यदि पाकिस्तान से कोई उत्पीड़ित अल्पसंख्यक भारत आया तो उसे नागरिकता दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने अपने शासनकाल में इन लोगों को नागरिकता देने की सोची तक नहीं। मोदी ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से आए उत्पीड़ित हिंदुओं, सिखों, जैनों, बौद्धों, पारसियों व इसाइयों को नागरिकता देकर सचमुच भारतीयता का सम्पादन किया है। अखिर गैर-मुस्लिम उत्पीड़ित लोगों को यदि भारत शरण नहीं देगा तो वे कहां जाएंगे। कांग्रेस समेत विपक्ष के भी हित में है कि वह सीएए को स्वीकार कर ले, नहीं तो जनता उनको अस्वीकार कर देगी।

- एमएम राजावत, शाजापुर

रूस-चीन दोरती

रूस और चीन दिन पर दिन करीब आ रहे हैं। इससे यह कहावत सही सिद्ध होती है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। पश्चिमी देश और नाटो मास्को व बीजिंग के लिए आज दुश्मन नंबर एक हैं। इसलिए दोनों तानाशाह- ब्लादिमीर पुतिन एवं शी जिनपिंग की दोस्ती दिन पर दिन परवान चढ़ रही है। शी जिनपिंग ने मास्को के दौरे में दोनों देशों के संबंधों में एक नए युग का वर्णन किया था, जबकि अक्टूबर 2023 में पुतिन ने बीजिंग का दौरा किया था तो शी ने दोनों नेताओं के बीच गहरी दोस्ती की बात की थी। अब एक बार पिछे पुतिन बीजिंग की यात्रा पर हैं। दोनों देश उन संबंधों को और गहरा करना चाहते हैं जो दो मास्को द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद घनिष्ठ हो गए हैं। अब देखना है कि चीन यूक्रेन पर रुसी आक्रमण के मामले में कब तक साथ देता रहेगा? चीन के पश्चिमी देशों से भी संबंध हैं और उसने रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने में अपनी मध्यस्थता का भी प्रस्ताव किया था। चीन-रूस की बढ़ती निकटता भारत की रणनीतिक स्वायत्ता के लिए भी परीक्षा की तरह है। देखना होगा कि चीन की भारत के प्रति आक्रामकता के मामले में रूस क्या दृष्टिकोण अपनाएगा। इसका भारत-अमेरिका संबंधों पर भी प्रभाव पड़ेगा।

- जंग बहादुर मिंद्र जमशेदपर

उत्तराखण्ड की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। 10 मई से यात्रा शुरू होने के बाद से 14 मई तक करीब पौने तीन लाख तीर्थयात्री यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जा चुके हैं। अभी तक 27 लाख लोग चारधाम यात्रा के लिए पंजीयन करवा चुके हैं। इस वर्ष 80 लाख लोगों के चारधाम यात्रा हेतु हिमालय पर पहुंचने की संभावना है। बेशक लागों में धार्मिक पर्यटन के प्रति प्रति रुक्णांक बढ़ा है क्योंकि पहाड़ों पर सड़कें अच्छी बन गई हैं तथा नई सुरंगें बनाने से मार्ग सुगम और छोटे हो गए हैं। देशभर में कई ट्रेवल्स एजेंसीज सक्रिय हो गई हैं और हेलीकॉप्टर के सभी टिकट अभी से बुक हो चुके हैं। जिन्हें बाद में भारी मुनाफा जोड़कर बेंच दिया जाएगा। गत वर्षों से हमने पहाड़ों पर भारी प्राकृतिक आपदाएं आते हुए देखी हैं। इसका सबसे बड़ा कारण पर्यटक सुविधाओं के लिए जा रहे निर्माण व अधिक भीड़ है। समय आ गया है कि सरकार को पहाड़ों पर जाने वाले पर्यटकों की संख्या नियंत्रित करनी होगी। पर्यटन व पर्यावरण संरक्षण में संतुलन धार्मिक स्थलों के दूरगामी विकास व स्थायित्व के लिए भी जरूरी है। - सुधाष बुड़वान वाला, रतलाम

पाठक अपना प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

